

/

[2023] 5 एस. सी. आर. 571

/

रोपपेन परिवहन सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। (2023 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 3006) फरवरी
07,2023

/

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, न्यायाधीशगण]

मोटर वाहन अधिनियम 1988: धारा 2(1 ए), 93,96-मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020-एग्रीगेटर का लाइसेंस-याचिकाकर्ता का महाराष्ट्र राज्य में दो पहिया वाहनों के लिए एक एग्रीगेटर की सेवा प्रदान करने का दावा-लाइसेंस देने के लिए आवेदन-आरटीओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह 2020 के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता था-उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई-हालाँकि, सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि क्या गैर-परिवहन वाहनों को एकत्रीकरण और सवारी पूलिंग सहित परिवहन वाहनों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए-उक्त उद्देश्य के लिए, एक समिति का गठन किया गया था-समिति के निर्णय तक, राज्य सरकार ने गैर-परिवहन वाहनों की पूलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिसूचना को चुनौती देने के लिए कोई झुकाव नहीं है-याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वैकल्पिक उपाय करने की स्वतंत्रता होगी-आरटीओ के आदेश की शुद्धता उच्च न्यायालय द्वारा समिति द्वारा पूरे मुद्दे की जांच करने के लिए लिए गए निर्णय से समाप्त हो जाती है, इससे पहले कि वह एकत्रीकरण और सवारी पूलिंग के उद्देश्यों के लिए गैर-परिवहन वाहनों के उपयोग पर निर्णय ले-आरटीओ के आदेश से संकेत मिलता है कि यह इस आधार पर पारित किया गया है कि 2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था-एक बार जब राज्य सरकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अंतिम निर्णय लेती है, तो याचिकाकर्ता ए.

/

/

/

/

/

/

/

572 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

राज्य सरकार के निर्णय में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बाद अपने कानूनी उपायों का पालन करें।

अतिरिक्त मौलिक/मौलिक न्यायनिर्णय:2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3006।

/

2020 की पी. आई. एल. संख्या 9775 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 07.03.2022 से।

सह

2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3007 और 3008,2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 95 और 142।

/

मुकुल रोहतगी, डी. एस. नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री फेरेस्ते सेठना, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री सुमन यादव, चैतन्य कौशिक, अभिषेक तिलक, सुश्री प्रप्रती केडिया, सुश्री शिवानी संघवी, सुयश भावे, मोहित तिवारी, आशीष मिश्रा, शुभम ऐरी, अमन दत्ता, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, गौरव अग्रवाल, सुश्री आकृति चौबे।अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

/

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री इंदिरा जयसिंह, सुश्री गायत्री सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, श्रीरंग बी. वर्मा, अभिकल्प प्रताप सिंह, भारत बागला, सुश्री कीर्ति दधीच, शांतनु शर्मा, भुवन कपूर, रोहित खरे, सुश्री श्रेया सक्सेना, सुश्री नूपुर कुमार, पारस नाथ सिंह, सुश्री रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर, रोहिन भट्ट, आनंद दिलीप लैंडगे, अक्षय देशमुख, अविनाश झा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

/

1. विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी गई।2. देरी को माफ कर दिया गया।

3. 2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3006 बॉम्बे में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 7 मार्च 2022 के एक अंतरिम आदेश से उत्पन्न होती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 95 और 2023 की 142 में याचिकाकर्ता महाराष्ट्र राज्य द्वारा 19 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती देना चाहते हैं। 2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3007 और 3008 बॉम्बे में उच्च न्यायालय के 20 जनवरी 2023 के निर्णय से उत्पन्न होती है।

/

/

/

रोपपेन परिवहन सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

4. मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 को 2019 के संशोधन अधिनियम 32 द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि इसके नियामक प्रावधानों के दायरे में एग्रीगेटर्स को समझा जा सके। धारा 2 (1 ए) में "एग्रीगेटर" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है परिवहन के उद्देश्य से एक यात्री के लिए चालक के साथ जुड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ या बाजार स्थान। धारा 93 अध्याय 5 का एक हिस्सा है जो परिवहन वाहनों के नियंत्रण से संबंधित है। एग्रीगेटर्स को शामिल करने के लिए 2019 में धारा 93 में भी संशोधन किया गया था। धारा 93, जैसा कि संशोधित किया गया है, इस प्रकार है:

/

"93. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एजेंट या कैनवासर या एग्रीगेटर।-

(1) कोई भी व्यक्ति स्वयं को संलग्न नहीं करेगा -

/

(i) एक एजेंट या प्रचारक के रूप में, सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री में या अन्यथा ऐसे वाहनों के लिए सीमा शुल्क का अनुरोध करने में, या

((ii) माल के डिब्बों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान को इकट्ठा करने, अग्रेषित करने या वितरित करने के व्यवसाय में एक एजेंट के रूप में,

/

(iii) एक एग्रीगेटर के रूप में, जब तक कि उसने ऐसे प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है और ऐसी शर्तों के अधीन है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

बशर्ते कि किसी एग्रीगेटर को लाइसेंस जारी करते समय राज्य सरकार ऐसे दिशानिर्देशों का पालन कर सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं:

/

बशर्ते कि प्रत्येक एग्रीगेटर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेगा। "5. संशोधित प्रावधान का प्रभाव यह है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना एग्रीगेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। लाइसेंस "ऐसे प्राधिकारी से होना चाहिए और ऐसी शर्तों के अधीन होना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।" धारा 93 (1) के पहले प्रावधान के संदर्भ में, राज्य सरकार, एक एग्रीगेटर को लाइसेंस जारी करते समय, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का "पालन" कर सकती है। धारा 96 राज्य सरकार को अध्याय 5 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

/

/

1 "अधिनियम "

/

/

/

[2023] 5 एस सी आर।

6. 2019 में अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केंद्र सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 तैयार किए। दिशानिर्देश एक प्रारंभिक बयान के साथ शुरू होते हैं कि उन्हें "परिवहन एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने और ऐसे एग्रीगेटर्स द्वारा संचालित व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में" जारी किया गया है। दिशा-निर्देश कानून के संशोधित प्रावधानों के संदर्भ में जारी किए गए हैं, जिसमें धारा 93 भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि किसी एग्रीगेटर को लाइसेंस जारी करते समय राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर सकती है। 2020 के दिशा-निर्देशों में विभिन्न प्रावधान हैं; उनमें से:

/

/

(i) खंड 4 जो एक एग्रीगेटर की पात्रता से संबंधित है; (ii) खंड 5 जो एक एग्रीगेटर को लाइसेंस देने के लिए शर्तें प्रदान करता है;

((ग) खंड 7 जो चालकों के संबंध में अनुपालन निर्धारित करता है;

/

((iv) खंड 8 जो वाहनों के संबंध में अनुपालन को स्पष्ट करता है;

(v) खंड 9 जो एग्रीगेटरों के ऐप और वेबसाइटों के संबंध में अनुपालन को संदर्भित करता है;

/

(vi) खंड 10 जो अन्य प्रावधानों के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन को निर्धारित करता है; और

(vii) खंड 13 जो किराए के विनियमन के लिए प्रावधान करता है।

/

7. मॉडल दिशानिर्देशों का खंड 15 नीचे दिया गया है: “15. एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन वाहनों का एग्रीगैटलॉन: (1) यातायात भीड़भाड़ और वाहन प्रदूषण में कमी के केंद्र और राज्य सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग के लिए, गैर-परिवहन वाहन पूलिंग एग्रीगेटर द्वारा प्रदान की जा सकती है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध न हो। इस तरह के निषेध के लिए तर्क लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जाए और राज्य सरकार के परिवहन पोर्टल पर उपलब्ध हो।

/

/

575

रोपपेन परिवहन सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

(2) इन दिशानिर्देशों में ऊपर उल्लिखित अनुपालनों के अलावा, जो लागू हो सकता है, गैर-परिवहन वाहनों को एकत्रित करने की मांग करने वाले एग्रीगेटर द्वारा निम्नलिखित का पालन किया जाएगा:

(क) एक कैलेंडर दिन में अधिकतम चार राइड-शेयरिंग इंटर-सिटी ट्रिप और एग्रीगेटर के साथ एकीकृत चालक के साथ प्रत्येक वाहन के लिए प्रति सप्ताह अधिकतम 2 राइड-शेयरिंग इंटर-सिटी ट्रिप की अनुमति होगी।

/

(ख) इस खंड 15 के अंतर्गत एकीकृत वाहन को कम से कम एक लाख रुपये का बीमा प्राप्त होगा। एग्रीगेटर के साथ एकीकृत मालिक या चालक के अलावा वाहन में सवारी-भागीदारों के लिए 5 लाख। "

/

8. खंड 15 (1) में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ संपत्ति के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हालांकि, खंड 15 यह भी निर्धारित करता है कि गैर-परिवहन वाहनों की पूलिंग एग्रीगेटर द्वारा प्रदान की जा सकती है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध न हो। इस तरह के निषेध के लिए तर्क राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और इसके परिवहन पोर्टल पर सुलभ होना चाहिए। 9. महाराष्ट्र सरकार ने अध्याय 5, विशेष रूप से धारा 93 (1) के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से एग्रीगेटर्स के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं। धारा 93 के पहले प्रावधान में कहा गया है कि किसी एग्रीगेटर को लाइसेंस जारी करते समय राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का एक प्रेरक मूल्य है। वे अनिवार्य नहीं हैं। जब राज्य सरकार धारा 96 के अंतर्गत अपनी शक्ति के अनुसरण में नियम बनाती है, तो वह उन दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रख सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा 2020 में विरचित गए हैं। धारा 93 (1) के पहले परंतुक और दिशानिर्देशों की साधारण शर्तों दोनों के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा इस बात पर विचार करते हुए किया जाना है कि लाइसेंस देना है या नहीं और धारा 96 के अंतर्गत सामान्य नियम बनाने की शक्ति के अनुसरण में नियम बनाने के संबंध में।

/

/

/

/

10. वर्तमान मामले में, 2023 की एसएलपी (सिविल) संख्या 3007 में पहला याचिकाकर्ता कानून के संशोधित प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक एग्रीगेटर है। यह मामला याचिकाकर्ताओं के राज्य भर में दो पहिया वाहनों के लिए एक एग्रीगेटर की सेवा प्रदान करने के दावे से संबंधित है।

/

576

/

[2023] 5 एस सी आर।

महाराष्ट्र से। पहले याचिकाकर्ता ने लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया। 21 दिसंबर 2022 के एक आदेश द्वारा, पुणे 2 के सड़क परिवहन अधिकारी ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि यह 2020 के दिशानिर्देशों के विभिन्न नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है। आर. टी. ओ. के आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया है:

“निर्णय:

/

1. टू व्हीलर बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस: मोटर वाहन समुच्चय नियम-2020 में महत्वपूर्ण मामलों में अपना टू व्हीलर बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस आवेदन दिनांक 30/11/2022 प्राप्त करने के लिए आवेदक मैसर्स रोपपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 4 (3), 5 (1), 5 (2), 5 (3), 7 (1) (सी), 7 (1), 7 (1) (जी), 7 (1) (एच), 7 (2) (ए), 7 (2) (बी), 7 (2) (सी), 7 (2) (एच), 7 (2) (के), 7 (2) (एम), 8 (2), 8 (3), 8 (5), 8 (6), 8 (10), 9 (1), 9 (2), 9 (3) और 13 पूर्ण नहीं हैं। सत्यापन के बाद, सिम्युलेटर और प्रेरण प्रशिक्षण की सुविधा की कमी, आंदोलनकारी लाइसेंस के बिना ऐप का संचालन, आधिकारिक हस्ताक्षर और मुहर के बिना प्रस्तुत किए गए सभी उपक्रम, वाहन चालकों के पर्याप्त अनुभव की कमी, परिवहन श्रेणी में नहीं आने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण आदि अधूरे पाए गए हैं। जमा किए गए दस्तावेजों में कुछ वाहनों के लिए बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। कानूनी दस्तावेज संलग्न नहीं हैं (कृपया पृष्ठ संख्या 5 पर तालिका संख्या 1 देखें)। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में सरकार या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा बाइक टैक्सी की ऐसी कोई योजना/योजना लागू नहीं की गई है। इसके अलावा, बाइक टैक्सी प्रकार का लाइसेंस/लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा, बाइक टैक्सियों के लिए कोई किराया संरचना नीति नहीं है। इसलिए, उपरोक्त कारणों से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने रैपन के दोपहिया बाइक टैक्सी आवेदन को अस्वीकार करने का फैसला किया। उक्त निर्णय के बारे में आवेदक (मैसर्स) को सूचित किया जाना चाहिए। रैपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 89, 90 और महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 97 के अनुसार, 30 दिनों के भीतर राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई (राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण) में अपील दायर की जा सकती है।

/

/

/

/

/

/

577

रोपपेन परिवहन सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

2. तिपहिया टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस: आवेदक मैसर्स रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2020 में तीन पहिया टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसका आवेदन दिनांक 30/11/2022 महत्वपूर्ण बिंदु जैसे बिंदु संख्या 4 (3), 5 (1), 5 (2), 5 (3), 7 (1) (बी), 7 (1) (सी), 7 (1) (डी), 7 (1) (ई), 7 (1) (एफ), 7 (1) (जी), 7 (1) (बी), 7 (2) (3), 7 (2) (बी), 7 (2) (सी), 7 (2) (एच), 7 (2) (के) आवेदन सत्यापन के बाद सिम्युलेटर और प्रेरण प्रशिक्षण सुविधा की अनुपस्थिति, सक्रियक लाइसेंस के बिना चलने वाला ऐप, आधिकारिक हस्ताक्षर और मुहर के बिना प्रस्तुत किए गए सभी उपक्रम, चालकों का अपर्याप्त अनुभव, वाहनों में कोई जी. पी. एस. प्रणाली नहीं, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, पुणे जानकारी जो किराए के आधार पर प्रदान नहीं की गई है, आदि खामियां पाई गई हैं। इसके अलावा, जमा किए गए दस्तावेजों में कुछ कानूनी दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाण पत्र, वाहन लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस, सार्वजनिक परिवहन सेवा बैज, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं हैं। (कृपया पृष्ठ संख्या 9 पर तालिका संख्या 2 देखें) "11. याचिकाकर्ताओं ने आरटीओ के फैसले की वैधता को चुनौती देने के लिए बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि 19 जनवरी 2023 को राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक अधिसूचना जारी की थी।

/

/

/

/

12. 19 जनवरी 2023 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पूरी तरह से नीचे दी गई है:

“गृह विभाग

/

मैडम कामा मार्ग

हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई 400 032।

दिनांक 19 जनवरी 2023। No.MVR-0821/C.R.95/TR-2 जबकि, भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन) के माध्यम से पत्र सं. एफ. संख्या 1601119/2019-टी, दिनांक 27 नवंबर 2020, ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 93 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अंतर्गत मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 (इसके बाद "उक्त दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) जारी किए;

/

/

578

/

[2023] 5 एस सी आर।

और जबकि, उक्त दिशानिर्देशों के खंड 11 और 15 में क्रमशः एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन वाहनों की सवारी पूलिंग और एकत्रीकरण का प्रावधान है। उक्त खंड 15 का उपखंड (1) राज्य सरकार को एग्रीगेटरों द्वारा गैर-परिवहन वाहनों की पूलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'तर्क' प्रदान करने का अधिकार देता है; और जबकि, यह देखा गया है कि परिवहन वाहनों के रूप में गैर-परिवहन वाहनों (दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया सहित) का उपयोग बहुत बढ़ रहा है और यात्रियों की गंभीर व्यावहारिक और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है और जो बड़े पैमाने पर आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

/

/

और जबकि गैर-परिवहन श्रेणी में पंजीकृत वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य के बाहर पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग वाहन एकत्रीकरण के उद्देश्य से भी किया जा सकता है और महाराष्ट्र राज्य में वैध परमिट पर चलने वाले वाहनों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकता है।

/

और जबकि, इस मुद्दे पर कि क्या गैर-परिवहन वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें एकत्रीकरण और सवारी पूलिंग शामिल है, इसके नियमों और शर्तों, ढांचे और दिशानिर्देशों के बारे में विस्तृत विचार की आवश्यकता है। इसलिए,

राज्य सरकार ने उक्त मुद्दों का अध्ययन करने और उनकी सिफारिशें देने के लिए समिति का गठन किया है।

/

और जबकि, सरकार महाराष्ट्र राज्य में आम जनता और बड़े पैमाने पर यात्रियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन वाहनों की पूलिंग को प्रतिबंधित करना समीचीन समझती है;

/

अब, इसलिए, महाराष्ट्र सरकार, मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 के खंड 15 के अनुसरण में, गैर-परिवहन वाहनों (दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया सहित) के उपयोग को एकत्रीकरण और सवारी-पूलिंग के उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित करती है।

/

आदेश द्वारा और के नाम पर

महाराष्ट्र के राज्यपाल

(आर. एम. होल्कर) सरकार के संयुक्त सचिव

/

579

रोपपेन परिवहन सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

13. उपरोक्त निर्णय द्वारा, राज्य सरकार ने नोट किया है कि क्या गैर-परिवहन वाहनों को एकत्रीकरण और सवारी पूलिंग सहित परिवहन वाहनों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा 12 जनवरी 2023 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति के निर्णय के आने तक, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में "आम जनता और बड़े पैमाने पर यात्रियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए" एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन वाहनों की पूलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 12 जनवरी 2023 को राज्य सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता एक पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और परिवहन विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। 14. उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर 2022 के आरटीओ के आदेश को चुनौती देने पर फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि वे 19 जनवरी 2023 की अधिसूचना को अलग से चुनौती देने या नहीं देने पर

विचार करेंगे और उस स्तर पर, चुनौती आरटीओ द्वारा जारी 21 दिसंबर 2022 के आदेश तक ही सीमित थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि 2020 के दिशानिर्देश राज्य सरकार के लिए एक निश्चित सीमा तक छूट देते हैं और वर्तमान समय में राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करने का अप्रतिबंधित अधिकार हो।

/

/

/

/

15. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि 2020 के दिशानिर्देशों की कई आवश्यकताएं जिनके आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था, व्यवहार्य नहीं हैं। महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने आग्रह किया है कि केंद्रीय दिशानिर्देशों का उद्देश्य यात्रियों और चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए कुछ आवश्यकताओं को लागू किया गया है।

/

16. 21 दिसंबर 2022 को लाइसेंस के लिए आवेदन को अस्वीकार करने वाले आर. टी. ओ. के आदेश की शुद्धता अब 19 जनवरी 2023 की अपनी अधिसूचना से उत्पन्न राज्य सरकार के बाद के निर्णय से प्रभावित है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि गैर-परिवहन वाहनों को एकत्रीकरण और सवारी पूलिंग सहित परिवहन वाहनों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर विस्तृत विचार किया जाना चाहिए। समिति के निर्णय के आने तक राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है

/

/

580

/

[2023] 5 एस सी आर।

एकत्रीकरण के उद्देश्य से गैर-परिवहन वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करना।

17. 19 जनवरी 2023 की अधिसूचना को उच्च न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी गई थी। राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अब इस न्यायालय के समक्ष दो याचिकाएं दायर की गई हैं। हम संविधान के अनुच्छेद

32 के अंतर्गत कार्यवाही में राज्य सरकार के गृह विभाग की 19 जनवरी 2023 की अधिसूचना को चुनौती देने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वैकल्पिक उपाय करने की स्वतंत्रता होगी। 21 दिसंबर 2022 के आर. टी. ओ. के आदेश की शुद्धता उस निर्णय से समाहित हो जाती है जो उच्च न्यायालय द्वारा समिति द्वारा पूरे मुद्दे की जांच करने के लिए लिया गया है, इससे पहले कि वह एकत्रीकरण और सवारी पूलिंग के उद्देश्यों के लिए गैर-परिवहन वाहनों के उपयोग पर निर्णय ले।

/

/

18. सुनवाई के दौरान, श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि एक ओर, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 57 में टिप्पणियों ने याचिकाकर्ताओं को 19 जनवरी 2023 की अधिसूचना को चुनौती देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है, लेकिन निर्णय के बाद के हिस्से में टिप्पणियाँ, अर्थात् पैराग्राफ 59 ऐसी चुनौती को रोक देगा।

/

/

19. उपरोक्त शिकायत को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि 19 जनवरी 2023 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय पैराग्राफ 59 में अपनी टिप्पणियों से खुद को बाध्य नहीं मानेगा। जो भी हो, बाद की टिप्पणियाँ केवल 21 दिसंबर 2022 के आर. टी. ओ. के निर्णय को चुनौती देने के संदर्भ में हैं, जो अकेले उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का विषय था।

/

20. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम याचिकाकर्ताओं को 19 जनवरी 2023 की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। उच्च न्यायालय 20 जनवरी 2023 के आक्षेपित निर्णय और आदेश में निहित टिप्पणियों से अप्रभावित ऐसी किसी भी चुनौती पर विचार करेगा।

/

21. 21 दिसंबर 2022 का आर. टी. ओ. का आदेश इंगित करता है कि यह इस आधार पर पारित किया गया है कि 2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। एक बार जब राज्य सरकार अंतिम ए लेती है

/

रोपपेन परिवहन सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्णय पर, याचिकाकर्ता राज्य सरकार के निर्णय में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बाद अपने कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने के हकदार होंगे। राज्य सरकार 31 मार्च 2023 को या उससे पहले अंतिम निर्णय लेगी। समिति 15 मार्च 2023 को या उससे पहले अपना अंतिम निर्णय लेगी ताकि राज्य सरकार को मार्च 2023 के अंत तक एक सुविचारित निर्णय लेने के लिए समय दिया जा सके।

/

22. तदनुसार याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

23. हस्तक्षेप के लिए आवेदन सहित लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

/

/

/

/

/